

राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आईआईटी इंदौर में समापन

प्रबंधन के माध्यम से ही नई पीढ़ी के लिए पानी सुरक्षित रख सकते

देश के प्रमुख संस्थानों से 150 से अधिक प्रतिभागियों ने चर्चा में भाग लिया

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क



पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता

सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर मनीष गोयल ने बताया तकनीकी सत्रों में जल गुणवत्ता, जल विज्ञान, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, उभरती प्रौद्योगिकियों और सतत जल अवसंरचना पर शोध प्रस्तुतियां शामिल थीं। पैनल चर्चा में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम), ग्रामीण-शहरी जल आपूर्ति असमानताओं और राष्ट्रीय जल नीति में सुधारों पर कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वहीं, प्रतिभागियों ने अंतःविषय सहयोग, केंद्र-राज्य समन्वय, सामुदायिक भागीदारी, जल साक्षरता विस्तार और जल प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए स्टार्ट-अप और उद्योग-अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय जल सम्मेलन-2026 सतत एवं अनुकूल भविष्य के लिए जल संसाधन का विकास विषय पर आयोजित किया गया। आयोजन मेहता फैमिली स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी (आईएनवाईएसए) के सहयोग से आईआईटी इंदौर में किया गया। देश के प्रमुख संस्थानों से 150 से अधिक प्रतिभागियों ने जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और सतत विकास पर केंद्रित चर्चा में भाग लिया।

सम्मेलन के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए देश की जल चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बात की। आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस. जोशी ने वैज्ञानिक और

प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों की तात्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जल हमारे भविष्य के लिए प्रमुख स्थान रखता है और केवल अनुसंधान, नवाचार और उत्तरदायी प्रबंधन के माध्यम से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को सुरक्षित कर सकते हैं। अकादमिक संस्थानों को साक्ष्य-आधारित समाधानों और सतत पद्धतियों के साथ इस मिशन का नेतृत्व करना चाहिए।

एकीकृत डिजिटल उपकरण है आवश्यक

आईएस जॉन किंगस्ली ने समन्वित कार्यवाही और समुदाय संचालित पहलों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वैज्ञानिक जल प्रबंधन को सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ चलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सतत जल संचालन के लिए विकेंद्रीकृत मॉडल, सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी और सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है। प्रोफेसर ए.के. नेमा ने जलवायु चालित जल चुनौतियों का समाधान करने में उन्नत प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा भारत के बदलते जल विज्ञान पैटर्न के लिए स्मार्ट, प्रौद्योगिकी-सक्षम जल प्रणालियों की आवश्यकता है। एआई से लेकर रिमोट सेंसिंग तक, दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत डिजिटल उपकरण आवश्यक हैं।

जल संसाधन शासन की मजबूत नींव

सम्मेलन में नीति निर्माता, प्रमुख शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी इंदौर के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल थे। मुख्य अतिथि, जॉन किंगस्ली (आईएस), सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, सम्मानित अतिथि, प्रोफेसर ए.के. नेमा, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी इंदौर के प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन अनुसंधान, नीति और समाज को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा, जिसने भारत में सतत, अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार जल संसाधन शासन की मजबूत नींव रखी।